5 देशभक्ति और सामाजिक सेवा से प्रभावित नेता

6 नक्सली आतंक से पूर्ण मुक्ति की ओर अवसर

7 जब सिस्टम सोया, तब एक जननायक जागा

RNI-MPBIL/2011/39805 DAVP/134083/25

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 35 प्रति सोमवार, 5 जनवरी 2026 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

नक्सलमुक्त भारत की दिशा में दो राज्यों की दो रणनीतियाँ, योजनाबद्ध पहल बनाम तात्कालिक निर्णय

छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री विजय शर्मा की गलत रणनीति के कारण हुआ हिडमा का एनकाउंटर

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

भारत लंबे समय से नक्सलवाद जैसी आंतरिक सुरक्षा चुनौती से जूझता रहा है। यह समस्या केवल कानून-व्यवस्था तक सीमित नहीं, बल्कि

विकास, विश्वास और संवाद से भी गहराई से जुड़ी हुई है। हाल के महीनों में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़- दो ऐसे राज्य, जो कभी नक्सली गतिविधियों से प्रभावित रहे। नक्सलमुक्त अभियान को लेकर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आए हैं। दोनों राज्यों में सरकारें एक ही राजनीतिक दल की हैं, किंतु नक्सल विरोधी अभियान की रणनीति, कार्यशैली और परिणामों में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। यही अंतर आज एक व्यापक विमर्श को जन्म दे रहा है।

(शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आलाकमान अब नहीं संभला तो फिर संभलने का अवसर नहीं मिलेगा

चरणदास महंत या टीएस सिंहदेव के "हाथ" में सौंपी जानी चाहिए छत्तीसगढ़ की कमान

भूपेश बघेल के बंटाधार से उबरने का अवसर

-विजया पाठक

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। धीरे-धीरे कांग्रेस का जनाधार घटता जा रहा है। कुशल नेतृत्व न होने से पार्टी बिखरने लगी है। न विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है और न ही किसान और युवाओं के मुद्दे उठाये जा रहे हैं। जिसके कारण लोगों के बीच भी पकड़ कमजोर हो गई है। भूपेश बघेल की दागदार छबि ने प्रदेश से कांग्रेस का बंटाधार कर दिया है। यहीं वह समय है जब प्रदेश में फिर से पार्टी को खड़ा किया जा सकता है। 2028 में अभी तीन साल का समय है। इन तीन साल में बेहतर और प्रभावी नेतृत्व कांग्रेस की वापसी करा सकता है। प्रदेश में डॉ. चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जैसे अनुभवी और बेदाग छबि के नेता मौजूद हैं। जो अपने दमखम से पार्टी को जिंदा करने की काबिलियत रखते हैं। डॉ. चरणदास महंत छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक अनुभवी और भरोसेमंद नाम हैं। वे सरल स्वभाव, स्पष्ट सोच और मजबूत संसदीय अनुभव के लिए जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री से लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष तक, उन्होंने हर भूमिका को गरिमा के साथ निभाया है। किसानों, आदिवासियों और आम जनता की आवाज बनकर वे लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अनुभव, संतुलन और नेतृत्व- यही डॉ. चरणदास महंत की पहचान है। डॉ. चरणदास महंत छत्तीसगढ़ की राजनीति में अत्यंत प्रतिष्ठित और वरिष्ठ नेता हैं। (शेष पेज 2 पर)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बना देश का अग्रणी खनन राज्य

-विजया पाठक

खनिज संपदा से समृद्ध छत्तीसगढ़ ने हाल के वर्षों में खनन क्षेत्र में जिस तरह की उल्लेखनीय प्रगति की है, उसने न केवल राज्य की आर्थिक तस्वीर बदली है, बल्कि उसे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद खनन गंतव्य के रूप में स्थापित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने खनिज प्रशासन को पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी नवाचार के मजबूत स्तंभों पर खड़ा करते हुए एक ऐसा प्रशासनिक मॉडल विकसित किया है, जो अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ की पहचान केवल एक खनिज समृद्ध राज्य के रूप में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, जिम्मेदार और सतत खनन के अग्रणी उदाहरण के रूप में उभर रही है। राज्य में विश्वस्तरीय लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, बाक्साइट और टिन अयस्क के साथ-साथ हालिया अन्वेषणों से क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक और रेयर अर्थ मिनरल्स की उपलब्धता प्रमाणित हुई है। यह उपलब्धि न केवल राज्य की भूवैज्ञानिक क्षमता को रेखांकित करती है, बल्कि भारत की रणनीतिक और औद्योगिक जरूरतों में छत्तीसगढ़ की भूमिका को भी और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। (शेष पेज 3 पर)

कर्ज़माफी से जनकल्याण तक: किसानों के हित में कमलनाथ का निर्णायक नेतृत्व

मंत्री विश्वास सारंग ने बगैर जानकारी के कर्जमाफी को फर्जी बताया, गरमाई सियासत

-विजया पाठक

मोहन सरकार के मंत्री विश्वास सारंग के कर्जमाफी पर दिये बयान के बाद प्रदेश में सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सूची तक जारी कर दी है। सारंग ने यहां तक कहा कि कमलनाथ सरकार ने फर्जी किसानों के कर्ज माफ किये। विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार की कर्जमाफी को 'फर्जी' बताकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कड़ा पलटवार करते हुए जिलेवार सूची जारी की है और किसानों का अपमान करने के लिए माफी मांगने की मांग की है। कहा कि बेहतर होगा झूठ और फरेब से प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के बजाय भाजपा किसानों से किए गए वादे निभाए जो उसने चुनाव के समय किए थे। सारंग ने यह बयान ऐसे समय दिया है जब प्रदेश का किसान अनेकों समस्याओं से जूझ रहा है। खाद बीज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और बयान से किसानों के जख्मों पर नमक डाला जा रहा है।

(शेष पेज 3 पर)

चरणदास महंत या टीएस सिंहदेव के "हाथ" में सौंपी जानी चाहिए छत्तीसगढ़ की कमान

(पेज 1 का शेष)

उनकी गिनती कांग्रेस पार्टी के अनुभवी और संतुलित नेतृत्व में होती है। सदन की मर्यादा, लोकतांत्रिक मूल्यों और निष्पक्ष निर्णयों के लिए उन्हें व्यापक सम्मान प्राप्त है। उनका पद और प्रतिष्ठा अनुभव, विश्वास और गरिमा का प्रतीक है। अब प्रदेश में महंत से बेहतर कोई विकल्प अब बचा नहीं है। गांधी परिवार से भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। भूपेश बघेल जब राज्य के सीएम बने थे उस समय चरण दास महंत भी रेस में शामिल थे।

आज भी पार्टी में मौजूद है कई काबिल नेता

प्रदेश में आज भी ऐसे कई नेता मौजूद हैं जिनको आलाकमान जिम्मेदारी सौंपकर पार्टी के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे को दूर कर सकती है। लेकिन बघेल के मोह की पट्टी आलाकमान की आंख में ऐसी बंधी है कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पार्टी आलाकमान को बघेल से जिम्मेदारी वापस लेकर चरणदास महंत को दी जा सकती है। क्योंकि यही वह नेता हैं जिन्हें कार्य करने का अनुभव भी है और बघेल से बिल्कुल अलग हटकर पार्टी लाइन पर काम करने का दमखम भी रखते हैं। इस विषय पर एक बार फिर पार्टी आलाकमान को विचार करने की आवश्यकता है।

महंत और सिंहदेव के पास है जनाधार

टीएस सिंहदेव और चरणदास महंत वे नेता हैं जिनके पास जनता का पर्याप्त जनाधार है। दोनों ही नेता सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों को साथ लेकर

चलने का माद्दा रखते हैं। इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि सिंहदेव ने उप मुख्यमंत्री रहते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों द्वारा किये जा रहे बघेल के विद्रोह को स्वतः आगे आकर संभाला और पार्टी की छवि को धूमिल होने से बचाया था। चरणदास महंत भी बेहद लोकप्रिय नेता हैं। यही कारण कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास अगर कोई लोकसभा सीट आई तो वह उनकी पत्नी ज्योत्सना महंत की सीट थी। क्योंकि इस सीट पर न सिर्फ ज्योत्सना ने बल्कि चरणदास महंत ने भी जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क साधा और जनाधार पाने में सफलता प्राप्त की।

अब नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पायेंगे

हम सभी ने भूपेश बघेल के हिटलरशाही रवैये को बहुत करीब से देखा है। ऐसे में कोई भी कार्यकर्ता अब उनके नेतृत्व में कार्य करने को इच्छुक नहीं है। हर कार्यकर्ता और पार्टी नेता अपने-अपने स्तर से पार्टी आलाकमान तक बघेल के कारनामों का पुल्लिंदा पहुंचा चुके हैं। ऐसे में अब वह समय आ गया है जब पार्टी आलाकमान को बघेल पर कोई कड़ा एक्शन लेकर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को छत्तीसगढ में पार्टी की कमान सौंपनी चाहिए। इससे पार्टी का कल, आज और कल में अवश्य सुधार आने की अपेक्षा है। क्योंकि अगर अब नहीं संभले तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में दोबारा कभी नहीं संभल पाएगी।

महंत और सिंहदेव जैसे अनुभवी नेताओं को मिली कमान तो छत्तीसगढ में वापस आ सकती है कांग्रेस

आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस को अनुभवी और जनाधार वाले नेताओं की जरूरत है। चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव जैसे अनुभवी और कर्मठ नेता यदि आज भी प्रदेश की कमान संभालते हैं तो निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस वापसी कर सकती है। क्योंकि आज भी प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार है। यदि इनको कमान सौंपी जाती है तो प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ शासन में आ सकती है। केवल अयोग्य नीति निर्धारक के कारण कांग्रेस वहां पर पैर नहीं जमा पा रही है। भूपेश बघेल ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और अत्याचार किया है उसका ही परिणाम है कि वह सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन कहते है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पार्टी हाईकमान आज भी चाहे तो राज्य के नीति निर्धारक को बदलकर कांग्रेस को पुनः प्रदेश में काबिज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रदेश में ऐसे कई नेता आज भी मौजूद हैं जिनका जनाधार काफी मजबूत है।

बघेल के पापों की सजा भुगत रही पार्टी

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बोये गये भ्रष्टाचार के बीज का परिणाम पार्टी को पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। बावजूद उसके कांग्रेस आलाकमान के कान में जूं तक नहीं रेंगी और उन्होंने अभी भी प्रदेश की कमान भ्रष्टाचारी और अनाचारी भूपेश बघेल को सौंप रखी है। बघेल ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान एक ऐसी चेडाल चौकड़ी का निर्माण किया था जिसने शासन की योजनाओं में घोटाले-भ्रष्टाचार करने का निर्णय लिया।

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से सफल हुआ नक्सलियों के खात्मे का अभियान

(पेज 1 का शेष)

मध्यप्रदेश में योजनाबद्ध रणनीति और नेतृत्व की स्पष्ट दृष्टि

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नक्सल विरोधी अभियान को एक स्पष्ट, मानवीय और रणनीतिक दिशा दी गई। बालाघाट जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सरकार ने केवल बल प्रयोग को ही समाधान नहीं माना, बल्कि संवाद, आत्मसमर्पण नीति और सटीक खुफिया तंत्र के समन्वय से काम किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नक्सलियों को या तो जीवित पकड़ा जाए या उन्हें आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया जाए। यह निर्देश अपने आप में यह दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य केवल मुठभेड़ों के आँकड़े बढ़ाना नहीं, बल्कि स्थायी शांति स्थापित करना था। इस रणनीति का परिणाम अभूतपूर्व रूप से सामने आया। मात्र 42 दिनों के भीतर 42 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह संख्या केवल एक आँकड़ा नहीं, बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक है जो सरकार की नीति और प्रशासनिक इच्छाशक्ति से बना। आत्मसमर्पण करने वाले कई नक्सलियों ने स्वीकार किया कि सरकार की पुनर्वास नीति, सुरक्षा की गारंटी और मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर उनके निर्णय का आधार बना। मध्यप्रदेश ने इस तरह नक्सलमुक्ति की दिशा में एक नया इतिहास रचा, जिसमें बल से अधिक बुद्धि और संवाद की भूमिका रही।

प्रशासन, पुलिस और समाज का समन्वय

मध्यप्रदेश मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता रही समन्वय। मुख्यमंत्री स्तर से लेकर जिला प्रशासन, पुलिस, खुफिया एजेंसियाँ और स्थानीय समाज- सभी को एक साझा लक्ष्य के तहत जोड़ा गया। योजनाबद्ध ढंग से क्षेत्रवार रणनीति बनाई गई, स्थानीय परिस्थितियों को समझा गया और हर कार्रवाई से पहले उसके दूरगामी परिणामों पर विचार किया गया। यही कारण है कि अभियान केवल सुरक्षा कार्रवाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विकास योजनाओं, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के विस्तार से भी जुड़ा रहा। इससे नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों का भरोसा सरकार पर और मजबूत हुआ।

छत्तीसगढ़ में कार्रवाई पर उठते सवाल

इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को लेकर कई प्रश्न खड़े हुए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार के भीतर ही गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर असहमति की आवाजें सुनाई दीं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री की पूर्ण जानकारी और व्यापक रणनीतिक योजना के बिना कुछ निर्णय लिए, जिनका परिणाम तात्कालिक रूप से हिंसक टकराव के रूप में सामने आया। विशेष रूप से हिडमा जैसे कुख्यात नक्सली नेता के संदर्भ में यह चर्चा तेज हुई कि यदि समग्र योजना और संवाद की संभावनाओं पर काम किया जाता, तो स्थिति अलग हो सकती थी। आलोचकों का कहना है कि बिना पर्याप्त तैयारी और दीर्घकालिक रणनीति के की गई कार्रवाइयाँ न केवल मानव जीवन के लिए जोखिमपूर्ण होती हैं, बल्कि सरकार की छवि और विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं।

राजनीतिक आरोप और प्रशासनिक छवि

छत्तीसगढ़ में हुई घटनाओं को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि तात्कालिक निर्णयों ने राज्य सरकार को अनावश्यक विवादों में घेर दिया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे कदमों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार की छवि को नुकसान पहुँचा और नक्सल विरोधी अभियान की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न लगे। यद्यपि सरकार की ओर से इन आरोपों का खंडन भी किया गया है, फिर भी यह बहस यह संकेत देती है कि आंतरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर समन्वय और नेतृत्व की एकरूपता कितनी आवश्यक है।

रणनीति बनाम तात्कालिकता

इन दोनों राज्यों के उदाहरण यह स्पष्ट करते हैं कि नक्सलवाद जैसी समस्या का समाधान केवल हथियारों से नहीं हो सकता। जहाँ मध्यप्रदेश में योजनाबद्ध, चरणबद्ध और संवाद-आधारित नीति अपनाई गई, वहीं छत्तीसगढ़ में तात्कालिक कार्रवाई की छवि उभरी। एक ओर आत्मसमर्पण के रिकॉर्ड बने, दूसरी ओर मुठभेड़ों और विवादों की चर्चा हुई। यह अंतर केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि वैचारिक भी है—कि राज्य नक्सलियों को केवल शत्रु के रूप में देखता है या भटके हुए नागरिक के रूप में, जिन्हें मुख्यधारा में लौटने का अवसर दिया जा सकता है।

नक्सल-मुक्ति की राह से मिली सीख और संदेश

नक्सल-मुक्त भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब सभी राज्य एक संतुलित नीति अपनाएँ- जहाँ सुरक्षा बलों की सशक्त भूमिका हो, वहीं संवाद, विकास और पुनर्वास की भी उतनी ही मजबूत व्यवस्था हो। मध्यप्रदेश का अनुभव यह बताता है कि राजनीतिक नेतृत्व की स्पष्ट सोच, प्रशासनिक अनुशासन और मानवीय दृष्टिकोण से बड़े बदलाव संभव हैं। वहीं छत्तीसगढ़ का प्रसंग यह चेतावनी देता है कि बिना समन्वय और योजना के उठाए गए कदम, भले ही उद्देश्य सही हों, लेकिन परिणाम जटिल हो सकते हैं। नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल एक राज्य या एक सरकार की नहीं, बल्कि राष्ट्र की साझा जिम्मेदारी है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के हालिया अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि नेतृत्व की भूमिका निर्णायक होती है। जहाँ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश ने संयम, रणनीति और संवाद से इतिहास रचा, वहीं छत्तीसगढ़ में उठे सवाल यह याद दिलाते हैं कि आंतरिक सुरक्षा जैसे विषय पर हर निर्णय सोच-समझकर, सामूहिक विमर्श और स्पष्ट योजना के साथ लिया जाना चाहिए। नक्सलमुक्त भारत की दिशा में यही संतुलित और दूरदर्शी मार्ग सबसे प्रभावी सिद्ध हो सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बना देश का अग्रणी खनन राज्य

(पेज 1 का शेष)

खनिज आधारित औद्योगिक विकास का केंद्र

आर्थिक दृष्टि से देखें तो खनन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में खनन का योगदान लगभग 10 प्रतिशत है, जबकि देश के कुल खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत तक पहुँच चुकी है। यह आँकड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राज्य अब केवल संसाधन प्रदाता नहीं, बल्कि खनिज आधारित औद्योगिक विकास का केंद्र बन रहा है। खनिज राजस्व में हुई ऐतिहासिक वृद्धि इस प्रगति का सबसे ठोस प्रमाण है। राज्य गठन के समय वर्ष 2000 में जहाँ खनिज राजस्व मात्र 429 करोड़ रुपये था, वहीं वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 14,592 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 25 वर्षों में 34 गुना से अधिक की यह वृद्धि किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि दीर्घकालिक नीति, प्रशासनिक सुधार और पारदर्शी व्यवस्था का संयुक्त फल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि खनिज संपदा का दोहन राज्य और समाज दोनों के हित में हो। खनिज नीलामी प्रक्रिया में भी छत्तीसगढ़ ने पारदर्शिता और निष्पक्षता की नई मिसाल कायम की है। खनन एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के संशोधित प्रावधानों के तहत लागू खनिज नीलामी नियम 2015 के अंतर्गत राज्य में अब तक 60 खनिज ब्लॉकों की सफल नीलामी की जा चुकी है। इनमें 15 लौह अयस्क, 14 बाक्साइट, 18 चूना पत्थर और 13 क्रिटिकल व स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 5 नए खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है, जिनमें चूना पत्थर, लौह अयस्क, स्वर्ण और बेस मेटल ब्लॉक सम्मिलित हैं। यह प्रक्रिया राज्य में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है।

दीर्घकालिक सहयोग हेतु एमओयू

खनन अनुसंधान और अन्वेषण को वैज्ञानिक आधार देने के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों आईआईटी मुंबई, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद और कोल इंडिया लिमिटेड के साथ दीर्घकालिक सहयोग हेतु एमओयू संपादित किए हैं। इस साझेदारी के माध्यम से क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की खोज को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गति मिली है। इससे न केवल संसाधनों की बेहतर पहचान संभव हुई है, बल्कि भविष्य की औद्योगिक और रणनीतिक जरूरतों के लिए राज्य खुद को तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि खनन से प्राप्त संसाधनों का लाभ सीधे प्रभावित क्षेत्रों और समुदायों तक पहुँचे। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की गाइडलाइन- 2024 के अनुरूप राज्य में जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2025 अधिसूचित किए गए हैं। अब तक राज्य को 16,119 करोड़ रुपये का डीएमएफ अंशदान प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत 1,05,653 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। इनमें से 74,454 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। ये कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आजीविका और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में खनन प्रभावित क्षेत्रों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। डीएमएफ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता और निगरानी को प्राथमिकता दी गई है। इसके लिए डीएमएफ पोर्टल 2.0 को लागू किया गया है, जिससे वित्तीय स्वीकृति, कार्य प्रबंधन और निगरानी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो गई है। इससे न केवल भ्रष्टाचार की संभावनाएँ घटी हैं, बल्कि जनहित कार्यों की गति और गुणवत्ता भी बेहतर हुई है।

राष्ट्रीय मॉडल राज्य के रूप में स्थापित

खनिज प्रशासन के डिजिटलीकरण की दिशा में खनिज ऑनलाइन 2.0 पोर्टल एक क्रांतिकारी पहल के रूप में सामने आया है। यह पोर्टल खनिज आवंटन, अनुमति, रॉयल्टी, निगरानी और रिपोर्टिंग की समस्त प्रक्रियाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर समाहित करता है। सुरक्षित, बहुआयामी और उपयोगकर्ता-मित्र इस प्रणाली ने छत्तीसगढ़ को खनन प्रबंधन में राष्ट्रीय मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राज्य में रेत खदानों का आबंटन भी अब पूर्णतः ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। एमएसटीसी के साथ किए गए एमओयू के तहत नई व्यवस्था में मानव हस्तक्षेप को समाप्त कर पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। इससे एक ओर राजस्व में वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण भी संभव हुआ है। सतत और जिम्मेदार खनन को प्रोत्साहित करने के लिए गौण खनिज नियम, 2015 के अंतर्गत स्टार रेटिंग प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत खनन पद्धति, पर्यावरण प्रबंधन, सुरक्षा उपाय और सतत विकास के मानकों पर खदानों का मूल्यांकन किया जाता है। अब तक 3 खदानों को 5-स्टार और 32 खदानों को 4-स्टार रेटिंग प्राप्त हो चुकी है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ सरकार केवल खनन को बढ़ावा नहीं दे रही, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी समान महत्व दे रही है।

सामाजिक विकास का मजबूत माध्यम

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि खनिज संपदा केवल राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि राज्य के सर्वांगीण विकास का आधार है। उनका मानना है कि यदि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीक और जनहित का समन्वय किया जाए, तो यह क्षेत्र रोजगार, आधारभूत संरचना और सामाजिक विकास का मजबूत माध्यम बन सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियाँ और क्रियान्वयन इसी सोच को प्रतिबिंबित करते हैं। कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने खनन क्षेत्र में नीतिगत सुधार, डिजिटल पारदर्शिता और सतत विकास के समन्वित प्रयासों से एक सशक्त और भरोसेमंद प्रशासनिक मॉडल प्रस्तुत किया है। यह प्रगति न केवल राज्य की आर्थिक मजबूती का संकेत है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संसाधनों का उपयोग यदि जिम्मेदारी और दूरदृष्टि के साथ किया जाए, तो विकास और जनकल्याण एक साथ संभव हैं। छत्तीसगढ़ की यह यात्रा आने वाले समय में देश के खनिज क्षेत्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

कमलनाथ की नीतियों से मजबूत हुआ मध्यप्रदेश का किसान

(पेज 1 का शेष)

जबकि सच्चाई यह है कि सारंग खुद भ्रष्टाचार, अनाचार और अनियमितताओं से लिप्त है। अनेकों मामलों में गोरखधंधा करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा भ्रष्टाचारी मंत्री कमलनाथ की योजना पर उंगली उठा रहा है। उनके 18 महीने के कार्यकाल को लेकर भले ही राजनीतिक मतभेद हों, परंतु यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि इस अवधि में सरकार ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को केंद्र में रखकर ठोस निर्णय लिए। विशेषकर किसानों को आर्थिक संबल देने के लिए किए गए प्रयासों ने प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया- विकास और संवेदनशील शासन की बहस। कमलनाथ सरकार का सबसे उल्लेखनीय कदम किसानों के कर्जमाफी कार्यक्रम के रूप में सामने आया। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने दो चरणों में लगभग 26 लाख 95 हजार 381 किसानों का कुल 11,646.96 करोड़ रुपये का कर्ज माफ़ किया। यह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि वर्षों से कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को आत्मसम्मान और राहत देने का प्रयास था।

सारंग के बयान पर कमलनाथ का पलटवार, जारी की कर्जमाफी की सूची

कर्जमाफी का यह मॉडल केवल आंकड़ों की राजनीति नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना से प्रेरित शासन का उदाहरण था। इसी पृष्ठभूमि में जब कमलनाथ की लोकप्रियता दिन-प्रतिदिन बढ़ती दिखाई दी, तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का स्वर भी तीखा हुआ। आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा ने भयवश झूठ और भ्रम का प्रपंच शुरू किया। सारंग पर यह आरोप सामने आए कि उन्होंने जनता के बीच कमलनाथ के कार्यों को लेकर असंतोष फैलाने की साजिश रची। यहां सवाल उठता है कि क्या लाखों किसान फर्जी हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं के माध्यम से कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों पर प्रश्नचिह्न लगाने का प्रयास किया गया, ताकि जनमत को भ्रमित किया जा सके।

षड्यंत्र के सहारे राजनीति कर रही भाजपा

आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता के बीच भ्रम फैलाने वाले लोग आत्ममंथन करें। जिन पर भ्रष्टाचार और झूठे प्रचार के आरोप हैं, उन्हें प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। लोकतंत्र में असहमति का अधिकार सबको है, लेकिन असत्य और षड्यंत्र के सहारे राजनीति करना जनहित के विरुद्ध है। किसानों के मुद्दे पर भाजपा की कथनी और करनी के बीच का अंतर भी अब उजागर हो रहा है। गेहूं और धान पर एमएसपी को लेकर किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। कमलनाथ ने स्पष्ट कहा है कि भाजपा ने चुनाव के समय किसानों से जो वादे किए थे, उन्हें निभाने के बजाय ध्यान भटकाने की राजनीति की जा रही है। परिणामस्वरूप, मध्यप्रदेश में किसानों की आमदनी घटती जा रही है। किसान खाद के लिए बुरी तरह परेशान है। लागत बढ़ रही है, समर्थन मूल्य और बाजार की सुनिश्चितता कमजोर है और नीति-निर्माण में किसान की आवाज़ हाशिये पर है।

किसानों को लाभकारी व्यवसाय से जोड़ने का था लक्ष्य

कमलनाथ सरकार के समय किसानों के लिए जो दृष्टिकोण अपनाया गया था, वह समावेशी था। केवल कर्जमाफी ही नहीं, बल्कि कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में सोच विकसित की गई। यह समझ थी कि किसान की समस्या एकल नहीं, बहुआयामी है बीज, खाद, सिंचाई, बाजार और मूल्य- हर स्तर पर सुधार की जरूरत है। अल्पकालिक राहत के साथ दीर्घकालिक समाधान की मंशा ही किसी भी सरकार की परिपक्वता को दर्शाती है। राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप चलते रहेंगे, परंतु जनता का विवेक अंततः परिणामों को देखता है। जिन परिवारों ने कर्जमाफी से राहत पाई, जिन महिलाओं और युवाओं को योजनाओं से लाभ मिला- उनके अनुभव किसी भी प्रचार से अधिक सशक्त हैं। यही कारण है कि कमलनाथ की लोकप्रियता आज भी चर्चा में है। यह लोकप्रियता किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक आधार पर टिकी हुई है।

राजनीति सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए हो

आज जब प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी और कृषि संकट से जूझ रही है, तब जरूरी है कि सरकारें झूठ और फ़रेब से लोगों को भ्रमित करने के बजाय वास्तविक समस्याओं का समाधान करें। भाजपा के लिए बेहतर होगा कि वह किसानों से किए गए वादों को पूरा करे एमएसपी की गारंटी दे, खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करे और किसान की आय बढ़ाने के ठोस कदम उठाए। राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, सेवा होना चाहिए। अंततः कमलनाथ के 18 महीने के कार्यकाल को किसी एक घटना या आरोप से नहीं, बल्कि उनके समग्र दृष्टिकोण और निर्णयों के प्रभाव से आंका जाना चाहिए। किसानों को दिया गया आर्थिक संबल, समाज के कमजोर वर्गों के लिए योजनाबद्ध पहल और संवेदनशील शासन ये सभी तथ्य इस बात की गवाही देते हैं कि विकास की राजनीति कैसे की जा सकती है। प्रदेश की जनता आज भी उसी राजनीति की अपेक्षा करती है ईमानदार, पारदर्शी और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्ध।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ

-प्रमोद कुमार

जगत प्रवाह. देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ीकैंट में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों के माल्टा एवं नींबू प्रजाति के फलों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर माल्टा एवं नींबू की खटाई सहित नींबू प्रजाति के फलों से बने विभिन्न उत्पादों का स्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की पहचान एवं परंपरा से जुड़ा है। राज्य की आर्थिकी व समृद्धि को सशक्त करने में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एप्पल मिशन व कीवी मिशन जैसी कई उल्लेखनीय शुरूआत की है। इसी तर्ज पर राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माल्टा मिशन की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के माल्टा की ब्रांडिंग व इसे बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य के हर जनपद में माल्टा महोत्सव का आयोजन इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य के माल्टा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

सम्पादकीय

मध्यप्रदेश में पर्यावरण संरक्षण नीति, प्रयास और भविष्य की दिशा

पर्यावरण संरक्षण आज केवल एक वैकल्पिक विषय नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व और सतत विकास की अनिवार्य शर्त बन चुका है। तेजी से हो रहे औद्योगीकरण, शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के बीच संतुलन बनाए रखना किसी भी राज्य के लिए बड़ी चुनौती है। मध्यप्रदेश, जिसे देश का "हरित हृदय प्रदेश" कहा जाता है, ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय और दूरगामी पहल की हैं। राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, जनभागीदारी आधारित अभियान और नवाचारपूर्ण योजनाएँ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी पहचान उसका विशाल वन क्षेत्र है। राज्य का लगभग एक-तिहाई भू-भाग वनों से आच्छादित है, जो जैव विविधता संरक्षण और जलवायु संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने वन संरक्षण अधिनियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ वनीकरण और पुनर्वनीकरण पर विशेष जोर दिया है। "अंकुर अभियान" के तहत पौधरोपण को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है, जिसमें नागरिकों को पौधा लगाने और उसकी देखभाल के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अभियान में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर पौधों की जियो-टैगिंग की गई, जिससे पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुआ।

जल संरक्षण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय किया है। राज्य में "जल गंगा संवर्धन अभियान" के माध्यम से तालाबों, बावड़ियों, नदियों और जलाशयों के पुनर्जीवन का कार्य व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार और नदियों के कैचमेंट एरिया में वृक्षारोपण जैसे कदम जल संकट से निपटने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। नर्मदा, क्षिप्रा और ताप्ती जैसी नदियों के संरक्षण हेतु विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य केवल स्वच्छता नहीं बल्कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह और पारिस्थितिकी को बनाए रखना है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। कई नगर निकायों में कचरे से खाद और ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाएँ संचालित हो रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और सार्वजनिक परिवहन के सुदृढ़ीकरण जैसे कदम पर्यावरण अनुकूल शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। इंदौर जैसे शहरों ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है, जो अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

जैव विविधता संरक्षण भी मध्यप्रदेश की पर्यावरण नीति का प्रमुख स्तंभ है। राज्य के राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य-जैसे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा—वन्यजीव संरक्षण के सफल उदाहरण हैं। बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा और गिद्ध संरक्षण परियोजनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त की है। विशेष रूप से बारहसिंगा संरक्षण कार्यक्रम ने यह सिद्ध किया कि वैज्ञानिक प्रबंधन और स्थानीय समुदाय की भागीदारी से विलुप्तप्राय प्रजातियों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।

पर्यावरण शिक्षा और जनजागरूकता के बिना संरक्षण के प्रयास अधूरे हैं। इस तथ्य को समझते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा दिया है। "एक पेड़ माँ के नाम" जैसे भावनात्मक अभियानों ने लोगों को प्रकृति से जोड़ने का कार्य किया है। इसके साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं और ग्राम सभाओं की भागीदारी ने संरक्षण प्रयासों को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान की है।हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी शेष हैं। औद्योगिक विस्तार, खनन गतिविधियाँ और बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण पर दबाव डालती हैं। ऐसे में आवश्यक है कि विकास परियोजनाओं में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को और अधिक कठोर व पारदर्शी बनाया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा, हरित तकनीक और सतत कृषि को प्रोत्साहन देकर ही दीर्घकालिक समाधान संभव है।

सियासी गहमागहमी

नए वर्ष की शुरुआत और दावोस की यात्रा

यह संयोग नहीं, बल्कि परंपरा बनती जा रही है। जैसे ही कैलेंडर बदला, वैसे ही सूट-बूट, फाइलें और विदेशी ठंड के लिए कोट तैयार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दावोस जाएंगे, जहाँ बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच विकास की गर्म बातें होंगी। वहाँ निवेश आएगा, एमओयू होंगे और कैमरों के सामने मुस्कानें भी चमकेंगी। प्रदेश में सड़क पर धूल उड़ रही होगी, लेकिन दावोस में "ग्लोबल कनेक्ट" का ग्लैमर दिखेगा। कहा जाएगा कि यह यात्रा मध्यप्रदेश के भविष्य के लिए जरूरी है। निवेशकों को लुभाने के लिए झीलों, जंगलों और खनिजों की तस्वीरें दिखाई जाएंगी, ताकि वे समझ सकें कि प्रदेश सिर्फ दिल से ही नहीं, संसाधनों से भी बड़ा है। लौटकर प्रेस नोट आएगा इतने हजार करोड़ के प्रस्ताव मिले। अब देखना यह होगा कि दावोस की ठंड में किए गए वादे प्रदेश की गर्म जमीन पर कितनी जल्दी पिघलते हैं।

जीतू पटवारी के नेतृत्व में MP कांग्रेस सुस्त क्यों है?

यह सवाल आज कार्यकर्ताओं से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों तक हर किसी की जुबान पर है। प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने से जो ऊर्जा, आक्रामकता और नई राजनीतिक धार की उम्मीद की जा रही थी, वह अभी तक जमीन पर साफ दिखाई नहीं देती। संगठन में बदलाव के दावे हुए, लेकिन जिलों और ब्लॉकों तक उनकी गूंज कमजोर रही। नेतृत्व का अर्थ केवल बयान देना नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं में जोश भरना और सरकार के खिलाफ सतत दबाव बनाना होता है। कांग्रेस फिलहाल प्रतिक्रियात्मक राजनीति में उलझी नजर आती है, जहाँ मुद्दे उठते तो हैं, लेकिन वे जनआंदोलन का रूप नहीं ले पाते। आपसी गुटबाजी, पुराने चेहरों का दबदबा और स्पष्ट रणनीति का अभाव भी सुस्ती का बड़ा कारण है। सवाल यह है कि जीतू पटवारी इस जड़ता को तोड़कर संगठन को सड़कों पर उतार पाएंगे या कांग्रेस यूँ ही मौके तलाशती रह जाएगी।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर-घर मातम है, गरीब बेबस है - और ऊपर से BJP नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में पूरा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया।

-सीवर पीने के पानी में कैसे मिला?
-समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई?
-जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी?

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

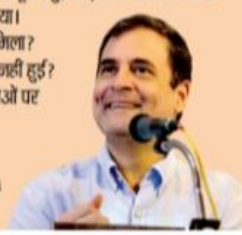

देश की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति भाजपा सरकार पूरी तरह असंवेदनशील है। प्राथमिक और जिला लेवल के अस्पतालों की बात छोड़ भी दें तो भी देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में ही डॉक्टरों की जबरदस्त कमी है।

-कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

देशभक्ति और सामाजिक सेवा की भावना से प्रभावित हैं गजेंद्र सिंह शेखावत

समता पाठक/जगत प्रवाह

भारत की राजनीति में अपनी प्रखर वक्तृत्व शैली और सक्रिय भागीदारी के लिए पहचाने जाने वाले गजेन्द्र सिंह शेखावत एक ऐसे राजनेता हैं, जिन्होंने छात्र राजनीति से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल तक का सफर तय किया है। वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और राजस्थान के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा, सामाजिक कार्यों में योगदान और जल संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके प्रयासों ने उन्हें देशभर में एक सम्मानित व्यक्तित्व बनाया है। इस लेख में हम गजेन्द्र सिंह शेखावत के जीवन, शिक्षा, करियर, उपलब्धियों और हालिया अपडेट्स के बारे में विस्तार से जानेंगे।

गजेन्द्र सिंह शेखावत की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

गजेन्द्र सिंह शेखावत का जन्म 3 अक्टूबर 1967 को राजस्थान के जैसलमेर जिले के मेहरोली गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता, शंकर सिंह शेखावत, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे, जिसके कारण परिवार को राजस्थान के विभिन्न हिस्सों में स्थानांतरित होना पड़ता था। इस वजह से गजेंद्र सिंह को अपनी प्रारंभिक शिक्षा विभिन्न स्कूलों में पूरी करनी पड़ी। उनके परिवार की देशभक्ति और सामाजिक सेवा की भावना ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया।

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) और मास्टर ऑफ फिलॉसफी (एम. फिल.) की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में रुचि दिखाई और यहीं से उनकी नेतृत्व क्षमता का विकास शुरू हुआ। गजेंद्र सिंह ने 1992 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की। यह जीत उनके राजनीतिक करियर की पहली सीढ़ी साबित हुई।

गजेन्द्र सिंह शेखावत का छात्र राजनीति से शुरुआत

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के साथ की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का एक अनुषांगिक संगठन है। 1992 में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में उनकी जीत ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बना दिया। इस दौरान गजेंद्र ने छात्रों के हितों के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाई और संगठनात्मक कौशल का परिचय दिया।

छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हुए गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आरएसएस और स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठनों के साथ भी काम किया। उनकी विचारधारा और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण ने उन्हें युवा नेतृत्व के रूप में स्थापित किया। इस अवधि में उन्होंने राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सामाजिक विकास के लिए 'सीमा जन कल्याण समिति' की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने सीमावर्ती गांवों में शिक्षा और सामुदायिक विकास के लिए कई स्कूल और छात्रावास स्थापित किए।

गजेन्द्र सिंह शेखावत की विदेश में खेती और वापसी

छात्र राजनीति में सफलता के बाद गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 1994 में एक अप्रत्याशित निर्णय लिया और राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बनाकर पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया चले गए। वहां उन्होंने जमीन खरीदकर खेती शुरू की। इस दौरान उन्होंने कृषि क्षेत्र में अपने अनुभव को समृद्ध किया, लेकिन उनके मन में देश सेवा और राजनीति की ललक बनी रही। गजेंद्र की यह यात्रा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव थी, जिसने उन्हें आत्मनिर्भरता और वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया।

गजेन्द्र सिंह शेखावत का केंद्रीय मंत्री के रूप में योगदान

गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने मंत्रालयों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। जल शक्ति मंत्री के रूप में, उन्होंने 'जल जीवन मिशन' को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था। इस मिशन के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा प्रदान की गई। गजेंद्र ने जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए, जिसने उन्हें पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में एक प्रमुख चेहरा बनाया।

जवाबदेही का अकाल: पाइपलाइनों में दौड़ता ज़हर

स्वच्छता का 'नंबर 1' तमगा और भागीरथपुरा की सिसकियाँ

आज की बात

प्रवीण कक्कड़

स्वतंत्र लेखक

देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा इंदौर को गर्व देता है। यह गौरव वर्षों की मेहनत, जनभागीदारी और प्रशासनिक प्रयासों का परिणाम है। लेकिन जब इसी शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण लोगों की असमय मृत्यु होती है और सैकड़ों नागरिक अस्पतालों में जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, तो यह तमगा आत्ममंथन की मांग करने लगता है। यह केवल एक मोहल्ले की त्रासदी नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक जवाबदेही पर लगा एक गंभीर प्रश्नचिह्न है।

खतरे की घंटी: पुरानी पाइपलाइनें और चूक

स्थानीय रिपोर्टों और चिकित्सकीय तथ्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह संकट आकस्मिक नहीं था। हैजा (Cholera) और गैस्ट्रोएन्टराइटिस (Gastroenteritis) जैसे जल-जनित रोगों का फैलना इस बात की पुष्टि है कि पेयजल आपूर्ति प्रणाली में गंभीर चूक हुई है। इंदौर का जल-आपूर्ति नेटवर्क कई दशकों पुराना है, जहाँ अनेक स्थानों पर सीवेज और पेयजल लाइनें एक-दूसरे के खतरनाक रूप से करीब हैं। लीकेज ऑडिट और नियमित वाटर सैंपलिंग जैसी प्रक्रियाएँ कागजों पर तो दर्ज हैं, लेकिन जमीन पर उनकी सुस्ती अब जानलेवा साबित हो रही है।

बिखरती जवाबदेही का ढाँचा

सवाल किसी एक विभाग या व्यक्ति पर उंगली उठाने का नहीं, बल्कि उस ढाँचे का है जहाँ जिम्मेदारी अक्सर बिखर जाती है। यदि अवैध निर्माण या गलत पाइपलाइन बिछाने का काम होता है, तो निगरानी के स्तर पर अधिकारी चुप क्यों रहते हैं? शहरी विकास का कड़वा सच यह है कि पहले सड़कें बनती हैं, फिर उन्हें खोदकर पाइपलाइनें डाली जाती हैं। समन्वय की यह कमी न केवल सार्वजनिक धन की बर्बादी है, बल्कि नागरिकों के जीवन के साथ सीधा खिलवाड़ भी है।

जिम्मेदारी का आत्ममंथन जरूरी

इस पूरी श्रृंखला में एक असहज सवाल हम खुद से भी पूछने से क्यों कतराते हैं? क्या हम एक ऐसे समाज में बदलते जा रहे हैं जो हादसों के बाद जागता है, रिपोर्टों के बाद विचलित होता है और कुछ दिनों में फिर सब भूल जाता है? जब मोहल्ले में अवैध निर्माण होता है, जब नालियाँ पेयजल पाइप से सटकर बहने लगती हैं, जब सड़क खोदकर महीनों छोड़ दी जाती है- तब हमारी आवाज क्यों नहीं उठती? क्या नागरिक होने का अर्थ केवल वोट डालना और फिर हर गलती के लिए व्यवस्था को कोसते रहना भर है?

संवैधानिक संकट और न्यायपालिका

संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है, जिसमें स्वच्छ जल अनिवार्य तत्व है। मानवाधिकार आयोग और न्यायालय द्वारा इस मामले में संज्ञान लेना इसी संवैधानिक चेतना की अभिव्यक्ति है। लेकिन प्रश्न यही है—क्या केवल नोटिस, जांच और स्टेटस रिपोर्ट से भविष्य की त्रासदियों को रोका जा सकेगा?

इंदौर की पहचान केवल पुरस्कारों और रैंकिंग से तय नहीं होगी। उसकी असली पहचान उसके नागरिकों के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन से बनेगी। भागीरथपुरा की यह त्रासदी एक अंतिम चेतावनी है व्यवस्था के साथ-साथ समाज को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। अब वक्त है कि व्यवस्था 'नंबर 1' के मंच से नीचे उतरकर, जन-हित की कठोर जमीन पर सच के साथ काम करे ताकि विकास की चमक में जीवन का अधिकार धुंधला न पड़ जाए। विकास की चमक तभी सार्थक है, जब वह अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सुरक्षा और विश्वास पहुँचा सके।

छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-दुर्गेश अरमोती

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर रेंज के बीजापुर और सुकमा जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए नक्सल विरोधी अभियान में निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 14 माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के कारण माओवादी नेटवर्क तेजी से कमजोर हो रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर अब विकास, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसरों के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन, केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व, सुरक्षा बलों की अदम्य वीरता एवं प्रतिबद्धता, संवेदनशील पुनर्वास नीति तथा बस्तर की जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा बलों के शौर्य को नमन करते हुए अभियान में शामिल सभी जवानों को बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जो लोग अब भी हिंसा का रास्ता चुन रहे हैं, वे आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा से जुड़ें, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएँ और सम्मानपूर्वक जीवनयापन करें अन्यथा राज्य शासन और सुरक्षा बल कानून एवं संविधान के अनुरूप अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की अंधेरी रात अब अपने अंतिम चरण में है और बस्तर में शांति, विश्वास और विकास का स्थायी सूर्योदय सुनिश्चित है।

नक्सली आतंक से पूर्ण मुक्ति की ओर लाल गलियारा

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

नक्सली अभियान के विरुद्ध ओडिशा में एक नई सफलता मिली है। कंधमाल जिले में चली एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने चार माओवादियों को मार गिराया। इनमें 1.20 करोड़ रुपए के इनामी ओडिशा राज्य समिति के प्रभारी 69 वर्षीय गणेश उइके और दो महिलाएं भी शामिल हैं। इससे पता चलता है कि समूचे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में महिलाएं भी सशक्त भूमिका निभा रहीं हैं। गणेश के मारे जाने के बाद अब ओडिशा नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से बढ़ेगा। इसके पहले बसव राजू और हिड़मा समेत नक्सली केंद्रीय समिति के एक दर्जन से अधिक शीर्ष माओवादी मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। इन नेतृत्व कर्ताओं की मृत्यु के बाद संगठनों का वर्चस्व खात्मे की ओर है।अतएव हम कह सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक माओवाद के समूल नाश का जो वचन दिया है, वह पूरा होगा।

माओवादी अर्से से देश में एक ऐसी जहरीली विचारधारा रही है, जिसे नगरीय बौद्धिकों का समर्थन मिलता रहा है। ये बौद्धिक नक्सली संगठनों को आदिवासी समाज का हितचिंतक मानते रहे हैं, जबकि जो आदिवासी नक्सलियों के विरोध में रहे, उन्हें इनकी हिंसक क्रूरता का शिकार होना पड़ा है। बावजूद इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि देश के वामपंथी दलों को कभी भी सुरक्षाबलों का नक्सलियों के खिलाफ चलाया जा रहा सफाये का अभियान पसंद नहीं आया। इसिलए जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था, तब उसका पुरजोर विरोध कांग्रेस समेत सभी सहयोगियों दलों ने किया, फलतः ऑपरेशन तो किसी नतीजे पर पहुंचे बिना ही दम तोड़ता चला गया, परंतु नक्सली संगठन के स्तर पर मजबूत और सुरक्षा बलों के लिए घातक होते चले गए।

नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। वामपंथी माओवादी उग्रवाद कभी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता रहा है। लेकिन चाहे जहां रक्तपात की नदियां बहाने वाले इस उग्रवाद पर लगभग नियंत्रण किया जा चुका है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार ने सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी है, जहां नक्सली अभी भी ठिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात कर चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में सैन्यबलों की अज्ञात क्षेत्र में पहुंच का मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अंतिम लड़ाई होने वाली है। मजबूत और कठोर कार्य योजना को अमल में लाने का ही नतीजा है कि इस साल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 2024 में 153 नक्सली मारे जा चुके हैं। शाह का कहना है कि 2004-2014 की तुलना में 2014 से 2024 के दौरान देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 53 प्रतिशत की कमी आई है। 2004 से 2014 के बीच नक्सली हिंसा की 16,274 वारदातें दर्ज की गई थीं, जबकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 सालों में इन घटनाओं की संख्या घटकर 7,696 रह गई। इसी अनुपात में देश में माओवादी हिंसा के कारण होने वाली मौतों की संख्या 2004 से 2014 में 6,568 थीं, जो पिछले दस साल में घटकर 1990 रह गई हैं और अब सरकार ने जो नया संकल्प लिया है, उससे तय है कि जल्द ही इस समस्या को निर्मूल कर दिया जाएगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से आतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है।

इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी का नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कार्यक्षेत्र वे आदिवासी बहुल इलाके हैं, जिनमें ये खुद आकर नक्सली बने हैं। इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पाना कठिन होता है। लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुखबिरों से सूचनाएं आसानी से हासिल कर लेते हैं। दुर्गम जंगली क्षेत्रों के मार्गों में छिपने के स्थलों और जलस्रोतों से भी ये खूब परिचित हैं। इसलिए ये और इनकी शक्ति लंबे समय से यहीं के खाद-पानी से पोषित होती रही है। हालांकि अब इनके हमलों में कमी आई है। दरअसल इन वनवासियों में अर्बन माओवादी नक्सलियों ने यह भ्रम फैला दिया था कि सरकार उनके जंगल, जमीन और जल-स्रोत उद्योगपतियों को सौंपकर उन्हें बेदखल करने में लगी है, इसलिए यह सिलसिला जब तक थमता नहीं है, विरोध की मुहिम जारी रहनी चाहिए। सरकारें इस समस्या के निदान के लिए बातचीत के लिए भी आगे आईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इन्हें बंदूक के जरिए भी काबू में लेने की कोशिशें हुई हैं। लेकिन नतीजे पूरी तरह अनुकूल नहीं रहे। एक उपाय यह भी हुआ कि जो नक्सली आदिवासी समर्पण कर मुख्यधारा में आ गए थे, उन्हें बंदूकें देकर नक्सलियों के विरुद्ध खड़ा करने की रणनीति भी अपनाई गई। इस उपाय में खून-खराबा तो बहुत हुआ, लेकिन समस्या बनी रही। गोया, आदिवासियों को मुख्यधारा में लाने से लेकर विकास योजनाएं भी इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अब तक सफल नहीं हो पाई हैं।

दरअसल, देश में अब तक तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर संवैधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उकसाने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रघाती बुद्धिजीवी पुख्ता सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की थी और गिरफ्तारियों को गलत ठहराया था। माओवादी किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जो भी उनके खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती हैं। लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकुश लगने जा रहा है।

व्यवस्था बदलने के बहाने 1967 में पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर नक्सलबाड़ी ग्राम से यह खूनी आंदोलन शुरू हुआ था। तब इसे नए विचार और राजनीति का वाहक कुछ साम्यवादी नेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और मानवाधिकारवादियों ने माना था। लेकिन अंततः माओवादी नक्सलवाद में बदला यह तथाकथित आंदोलन खून से इबारत लिखने का ही पर्याय बना हुआ है। जबकि इसके मूल लक्ष्यों में नौजवानों की बेकारी, बिहार में जाति तथा भूमि के सवाल पर कमजोर व निर्बलों का उत्थान, आंध्र प्रदेश और अविभाजित मध्यप्रदेश के आदिवासियों का कल्याण तथा राजस्थान के श्रीनाथ मंदिर में आदिवासियों के प्रवेश शामिल थे। किंतु विषमता और शोषण से जुड़ी भू-मण्डलीय आर्थिक उदारवादी नीतियों को जबरन अमल में लाने की प्रक्रिया ने देश में एक बड़े लाल गलियारे का निर्माण कर दिया था, जो पशुपति (नेपाल) से तिरुपति (आंध्रप्रदेश) तक जाता है। इस पूरे क्षेत्र में माओवादी वाम चरमपंथ पसर गया था। इसने नेपाल, झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के एक ऐसे बड़े हिस्से को अपनी गिरफ्त में ले लिया था जो बेशकीमती जंगलों और खनिजों से भरे हैं। छत्तीसगढ़ के बैलाडीला में लौह अयस्क के उत्खनन से हुई यह शुरुआत ओड़ीसा की नियमगिरी पहाड़ियों में मौजूद बॉक्साइट के खनन तक पहुंच गई थी। यहां आदिवासियों की जमीनें वेदांता समूह ने अवैध हथकंडे अपनाकर जिस तरीके से छीनी थीं, उसे गैर कानूनी खुद देश की सर्वोच्च न्यायालय ने ठहराया था।

हालांकि खबरें तो यहां तक हैं कि पाकिस्तान और चीन माओवाद को बढ़ावा देने की दृष्टि से हथियार पंहुचाने की पूरी एक श्रृंखला बनाए हुए हैं। चीन ने नेपाल को माओवाद का गढ़ ऐसे ही सुनियोजित षडन्त्र रचकर वहां के हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ध्वस्त किया। नेपाल के पशुपति से तिरुपति तक इसी किस्म के माओवाद को आगे बढ़ाने की मानसिकता को तथाकथित शहरी बौद्धिकों ने प्रोत्साहित किया। किंतु केंद्र नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से राष्ट्र-राज्य की परिकल्पना को चुनौती बने इस चरमपंथ के दिन गिनती के रह गए हैं।

पर्यावरण पर विकास का अत्याधिक बोझ

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

पर्यावरण और विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। एक देश की आर्थिक तरक्की भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। संपन्नता और विकास एक देश के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है किंतु इस विकास का आनंद लेने के लिए यह जरूरी है कि हम पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण को विशेष महत्व दें। पर्यावरण और विकास का संतुलन बना कर के ही हम तरक्की का आनंद ले पाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित कर पाएंगे। आज पर्यावरण विनाश का सबसे बड़ा कारण तथाकथित विकास है जिसके पीछे इंसान अंधाधुन भागे चला जा रहा है। प्रकृति ने मानव को अन्य जीवों की अपेक्षा एक विलक्षण वस्तु "मस्तिष्क" प्रदान किया था जिसका इसने दुरुपयोग किया। उसने अपने जैविक और भौतिकवाद के चक्कर में पड़कर और स्वार्थ लोलप्तावश सम्पूर्ण प्रकृति और पर्यावरण संकलन का क्षत विक्षप्त कर दिया। अबाध रुप से बढ़ती जनसंख्या और उसी गति से समाप्त होती प्राकृतिक संपदाएं और संसाधन हमारे विनाश के सूचक हैं। विज्ञान की निरंतर भागदौड़ तथा मानव का भौतिकवाद प्राकृतिक संकलनों, संसाधनों को तीव्रता से नष्ट करता जा रहा है। किंतु जानते हुए भी इस पर हम सोच नही रहे हैं। हम दावे जितनी कर लें लेकिन असल में पर्यावरण की सूची में दुनिया के 180 देशों में भारत की स्थिति बहुत खराब है। पर्यावरण को लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने इसका खुलासा करते हुए कहा है कि देश में पर्यावरण सुधार के दावों के बावजूद हालत बेहद खराब है। विडंबना है कि डेनमार्क और ब्रिटेन जैसे देश 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अमेरिका, चीन, भारत और रूस जैसे देश बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं।

यह सच है कि पृथ्वी तभी बचेगी जब पर्यावरण विकास का आधार बनेगा। जहां तक हरित संपदा का सवाल है उसके बारे में सरकार लगातार बढ़ोतरी का दावा करते नही थकती जबकि असलियत में इंसान और पेड़ों के अनुपात की वैश्विक सूची में भारत सबसे निचले पायदान पर है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति पेड़ों की तादाद 28 ही है। 2020 में बीस फीसदी से ज्यादा पेड़ पौधों का दायरा सिमट गया। आई एस एफ आर के अनुसार हर साल देश में 22 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। जबकि कोरोना ने ऑक्सिजन और पेडों के महत्व का आभास सबको बखूबी करा दिया है। फिर भी सरकार विकास के नाम पर पेड़ों को निर्बाध कटाव पर आमदा है। उस स्थिति में जबकि देश में हरित संपदा की दृष्टि से केवल 3, 518 करोड़ ही पेड़ बचे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रति वर्ग किलोमीटर देश में कुल 11,109 पेड़ है। ग्लोबल रैंकिंग की दृष्टि से पेडों के लिहाज से भारत का स्थान दुनिया में 17वां, क्षेत्रफल के हिसाब से 125वां है। जबकि दुनिया के परिपेक्ष में देखें तो 69, 834करोड़ पेडों के साथ रूस पहले, 36,120 करोड़ पेडों के साथ कनाडा दूसरे, 33,316 करोड़ पेडों के साथ ब्राजील तीसरे, 22,286 करोड़ पेडों के साथ अमेरिका चौथे और 17,753 करोड़ पेडों के साथ चीन पांचवें पायदान पर है। समाज और सरकार को मिलकर वृक्षारोपण संस्कृति का विकास करना होगा, जिसके फायदे कई स्तरों पर समाज को मिलेंगे। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। वहीं जंगलों का विस्तार प्राणवायु के साथ साथ आर्थिक समृद्धि का भी संबल बनेगा।

अगर उत्तराखंड को लें तो वहां देवदार के पेडों का कटान जारी है। बीते वर्षो में वहां विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी कर हरित संपदा, पानी और मिट्टी की अंधाधुंध बर्बादी की जा रही है। ऑल वेदर रोड के नाम पर वहां देवदार के सवा लाख पेड़ काट दिए गए है और कई पेडों के कटने की संभावना है। हालाकि सरकार ने भरोसा दिलाया है कि जितने पेड़ काटे जायेंगे उससे ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नही पाता। वह केवल रिकॉर्ड तक सीमित रहता है हकीकत में नही होता। यह सारा क्षेत्र राई, कैल, देवदार, धुनेर आदि शंकुधारी दुर्लभ वन प्रजातियों से भरपूर है। ग्लेशियरों के टूटने पर उसके दुष्परिणाम से बचाने में यही प्रजातियां प्रमुख भूमिका निभाती हैं। देवदार के पेड़ हिमालय और गंगा के सशक्त पट्टी हैं। ग्लेशियरों के तापमान नियंत्रित करने में इसका अहम योगदान है।

विकास, जिसका लक्ष्य बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाना है, पर्यावरण पर बहुत दवाब पड़ता है। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में पर्यावरण संसाधनों की मांग पूर्ति से कम थी। अब विश्व के समक्ष पर्यावरण संसाधनों की बढ़ती मांग है लेकिन उनकी पूर्ति अत्यधिक उपयोग व दुरुपयोग की वजह से सीमित है। विकास का लक्ष्य उस प्रकार के विकास का संवर्धन है, जोकि पर्यावरण समस्याओं को कम करे और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करे।

भागीरथपुरा त्रासदी और जन-सेवा का 'कैलाश' मॉडल : जब सिस्टम सोया, तब एक जननायक जागा

-राजेश चतुर्वेदी

जगत प्रवाह. इंदौर। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल वितरण से हुई मौतों और बीमारी ने शहर की "स्मार्ट सिटी" छवि पर एक बदनुमा दाग लगा दिया। जहां एक ओर प्रशासनिक अमला अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ता नजर आया, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली जननायक वह है जो प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि पीड़ा देखता है। इस पूरी घटना का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यदि विजयवर्गीय समय रहते मोर्चा नहीं संभालते, तो स्थिति अत्यंत भयावह हो सकती थी।

संकटमोचक की भूमिका में कैलाश विजयवर्गीय: त्वरित कार्रवाई और संवेदनशीलता

जिले के प्रभारी मंत्री और शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी नदारद थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पूर्व निर्धारित सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। उनका उद्देश्य कोरी संवेदना प्रकट करना नहीं था, बल्कि समाधान देना था। विजयवर्गीय ने वातानुकूलित कमरों से निर्देश देने के बजाय प्रभावित क्षेत्र में ही अपना 'अड्डा' जमा लिया। उनकी इस जमीनी सक्रियता ने जनता को कोरोना काल के उस दौर की याद दिला दी, जब वे अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद कर रहे थे।

दोहरी रणनीति: एक तरफ वे अस्पतालों में जाकर बीमारों की मिजाजपुरसी कर रहे थे और डॉक्टरों का हौसला बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले अफसरों की क्लास भी लगा रहे थे। यह संतुलन ही कुशल प्रशासन की निशानी है।

अधिकारियों की लापरवाही स्पष्ट थी: दूषित पानी की शिकायतों को समय रहते अनसुना करना ही इस त्रासदी का मुख्य कारण बना। ऐसे में विजयवर्गीय का हस्तक्षेप ही वह ढाल बना जिसने प्रशासन की नाकामी के असर को कुछ हद तक कम किया। भागीरथपुरा की घटना ने प्रदेश की शासन पद्धति पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं। यह स्पष्ट है कि वर्तमान में शासन पद्धति 'व्यक्ति केंद्रित' होती जा रही है, जहां शीर्ष नेतृत्व की 'मैं ही सर्वोपरि' वाली शैली ने निचले स्तर पर जनप्रतिनिधियों को लाचार बना दिया है।

शिक्षा विभाग की निरंतर अनदेखी, बीईओ-बीआरसी कार्यालय संचालन व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह

-बद्रीप्रसाद कौरव

जगत प्रवाह. गाडरवारा। विकासखंड केंद्र पर साईखेड़ा ब्लॉक की विधिवत इमारत मौजूद होने के बावजूद वर्षों से कार्यालय गाडरवाड़ा नगर के विभिन्न स्कूल भवनों से संचालित किए जा रहे हैं। कभी पुरानी पुत्रीशाला, कभी वीटीआई स्कूल तो कभी पीएमश्री कन्या नवीन विद्यालय के कक्षों पर अतिक्रमण कर अधिकारी कार्य कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सभी ब्लॉक स्तरीय कार्यालय साईखेड़ा में संचालित होते हैं, तो शिक्षा विभाग का बी ई ओ कार्यालय वहां जाने से परहेज क्यों कर रहा है। इस जिद के कारण ब्लॉक के शिक्षक और ग्रामीण जनता बेवजह गाडरवाड़ा आने को मजबूर हैं। टीसी, दाखिल-खारिज, अंकसूची सुधार जैसे कार्यों के लिए लोगों को अधिकारियों की खुशामद करनी पड़ रही है। चिंताजनक बात यह है कि यह पूरा मामला क्षेत्रीय विधायक और शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में हो रहा है, फिर भी प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। इस मामले ने पूर्व समय में भी टूल पकड़ा था मगर विभागीय साठ-गांठ के चलते मामला दबा दिया जाता है और जिला शिक्षा कार्यालय व विभाग चुप्पी के साथ यह विवादास्पद मामले सिंदूरी बनाए हुए है अब देखना है कि कब तक ऐसे ही जनता को मजबूरी का यूंही और सामना करना पड़ेगा।

नव वर्ष के उपलक्ष्य में एसबीआई शाखा टिमरनी में गोपाला भजन मंडल द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा टिमरनी में दिनांक 1 जनवरी 2026 को नववर्ष के उपलक्ष्य पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शाखा के अधिकारी मुख्य प्रबंधक नितिन सेलट, क्षेत्राधिकारी आलोक गौतम, तिरूपति गुगुलोतु और अभिषेक गुप्ता, सेवा प्रबंधक कमलेश बिरला और अन्य स्टाफ आनंद मौर्या, राहुल राजपूत, मोहित खत्री, मुदस्सर अली, मृणाली जाट, संग्राम सिंह, नवीन पाटिल और गणेश सैनी सहित सभी कर्मचारियों एवं स्थानीय नागरिकों ने श्रद्धापूर्वक सहभागिता की। सुंदरकांड पाठ के दौरान भगवान श्रीराम एवं हनुमान जी की भक्ति से शाखा परिसर भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य प्रबंधक द्वारा सभी के मंगलमय जीवन एवं समाज में सद्भावना बनाए रखने की कामना की गई।

अन्नदाता

मध्यप्रदेश शासन

पराली न जलाएं, धरती और जीवन बचाएं

उपजाऊ शक्ति में वृद्धि | प्रदूषण से मुक्ति | अर्थव्यवस्था को गति

मिट्टी के रूप में मिले वरदान को नष्ट होने से बचाएं

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री — नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ये विकल्प अपनाएं

हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम यंत्र का उपयोग

हैप्पी सीडर और सुपर सीडर का उपयोग कर सीधी बोनी

रीपर से कटाई के बाद जीरो टिलेज मशीन से सीधे बोनी

बेलर मशीन का उपयोग कर धान की पराली और मक्के के तने के बेल्स बनाएं

धान की पराली का प्लेट्स, ब्रिक्स और बायो फर्टिलाइजर के निर्माण में उपयोग

प्राकृतिक खेती को अपनाएं

मिट्टी की सतह पर सूक्ष्म जीवों के बढ़ावे से मिट्टी की उर्वर शक्ति में वृद्धि

रासायनिक पदार्थों से मुक्त होने से कैंसर जैसी घातक बीमारियों से मुक्ति

प्राकृतिक खेती से उत्पादन में कोई कमी नहीं

R.O. No. : D19257/25

आइये, स्वस्थ मिट्टी, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन के लिए पराली न जलाने का प्रण लें....

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। **संपादक : विजया पाठक।** ***RNI-MPBIL/2011/39805*** समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)